नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला या धर्मों का ठेला

15 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला-2014 शुरू हो चुका है जो 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार का मेले का केन्द्र बाल साहित्य को रखा गया है। यह निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है। मेले में काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चो से सम्बन्धित पुस्तकें भी उपलब्ध थी। लेकिन जब भारत के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड-सी.बी.एस.ई.की परीक्षायें सिर पर हों, ऐसे समय में बाल साहित्य को केन्द्र में रखकर मेला आयोजित करना बड़ा अखरा। बेहतर होता अलग से विश्व बाल पुस्तक मेले का आयोजन गर्मी की छुट्टियों में किया जाता।

लेकिन उससे भी ज़्यादा अखरने वाली बल्कि कहिए चिन्ता की बात विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की मेले में बढ़ती भागीदारी है। इसाईयों के धर्मग्रन्थ बाइबिल खरीदने के लिए उनके स्टाल पर आने का न्यौता देने वाला पैम्फलैट बांटते हुये मेले में सैंकड़ों लोग घूम रहे थे। उधर वैदिक धर्म ग्रन्थों के स्टाल का प्रचार करने वाले भी सैंकड़ों पोस्टर मेले में जगह-जगह लगे थे। वैसे तो ये सभी धर्मग्रन्थ पहले भी पुस्तक मेले में उपलब्ध रहे हैं लेकिन उनका ऐसा प्रचार पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने भी कई स्टाल लगाये हुये हैं। अनेकों मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने भी अपने स्टाल लगाये हुये हैं। इन धार्मिक स्टालों में पुस्तकें कम और अन्य धार्मिक सामान बिक्री के लिये ज़्यादा उपलब्ध था। इसके अलावा योगदा सत्संग सोसायटी, 'इस्कान' आदि के भी स्टाल मेले में लगे हुये थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि सिरसा के 'डेरा सच्चा सौदा' जैसे संगठन को भी आयोजकों ने मेले में स्टाल लगाने की इजाजत दे दी जिसके प्रमुख के ऊपर बलात्कार व हत्या जैसे घिनौने व जघन्य आरोपों में अदालत में मामले विचाराधीन हैं। इसके अलावा बौद्धों, जैनियों, रविदास, बाल्मिकी आदि से सम्बन्धित धार्मिक संस्थाओं ने भी स्टाल लगाये हुये थे। हो सकता है बहुत सारे और भी ऐसे स्टाल मेले में लगे हों जिनको यह लेखक समय की कमी और मेले के विस्तार को देखते हुये न देख पाया हो।

हाल न. 2 व 3 में लगे एक स्टाल पर तो उस समय बड़ी ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब वेदों और कुरान के समर्थकों के बीच बहस ने गरमा-गरमी पैदा कर दी। यह स्टाल एक ऐसी संस्था ने लगाया था जो वेदों को भगवान या अल्ला का दिया हुआ पहला ग्रन्थ और कुरान को आखिरी ग्रन्थ होने का प्रचार कर रहे थे। इस स्टाल में लगे पोस्टरों आदि से स्पष्ट था कि यह स्टाल सिर्फ इस संस्था ने प्रचार के लिये लगाया था न कि किसी पुस्तक की बिक्री के लिये।

दुख की बात ये भी थी कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में लगने वाले इस एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हिन्दी के लिये सिर्फ़ एक ही हाल है, जिसमें भी कई स्टालों पर धर्म प्रचारकों ने कब्ज़ा कर रखा था। इसी हाल में की गई एक पुस्तक के लोकार्पण की उद्घोषणा में जब उद्घोषक को लोकार्पण को 'लोकापरण' कहते सुना तो मन में बड़ा क्षोभ हुआ।

दुख की बात ये भी थी कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में लगने वाले इस एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हिन्दी के लिये सिर्फ़ एक ही हाल है, जिसमें भी कई स्टालों पर धर्म प्रचारकों ने कब्ज़ा कर रखा था। इसी हाल में की गई एक पुस्तक के लोकार्पण की उद्घोषणा में जब उद्घोषक को लोकार्पण को 'लोकापरण' कहते सुना तो मन में बड़ा क्षोभ हुआ। इसके अलावा भी उच्चारण की अनेकों गलतियां उस उद्घोषणा में थी। हिन्दी की ऐसी दुर्दशा देख कर मन दुख से भर उठा। सभी हालों में ज़्यादा पुस्तकें अंग्रेजी की ही थी। बाल साहित्य के नाम पर स्कूल और कॉलेजों की कोर्स की किताबों की भरमार थी। बड़ी संख्या में कॉमिक्स व बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिये सचित्र पुस्तकें भी उपलब्ध थी। कुल मिलाकर साहित्य के नाम पर अंग्रेजी में ही थोड़ी बहुत पुस्तकें उपलब्ध थी। लेकिन मेले में साफ़-सफ़ाई और खाने का ठीक-ठाक प्रबन्ध था। हालाकि मेले के अन्दर परिवहन की मुफ़्त व्यवस्था की गई थी लेकिन पीने के लिये पानी मुफ़्त में कहीं भी उपलब्ध नहीं था। पुस्तक मेला होने के बावजूद प्रवेश शुल्क लगाने की बात भी बहुत अखरी। खाने-पीने के महंगे इन्तजाम और प्रवेश शुल्क से लगा कि सरकार इस मेले को भी धीरे-धीरे अमीरों तक ही सीमित कर देना चाहती है।

लेकिन मेले के आयोजकों नैशनल बुक ट्रस्ट आदि ने यदि इस पुस्तक मेले को धर्म प्रचार का अखाड़ा बनाने की कोशिश पर लगाम नहीं लगाई तो जल्दी ही इस मेले में सांप्रदायिक दंगा होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

-अजातशत्रु

हड्डा सरकार की मुफ़्त इलाज योजना मात्र एक छलावा

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री मुफ़्त इलाज योजना जो कि 1 जनवरी 2014 से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों में लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों में फ्री इलाज, दवाई व सभी तरह की जांच शामिल है। जिसके चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह-खान को भी 40 लाख रुपये की राशि दी गई। बावजूद इसके आज भी अस्पताल में आंखों की जांच करने वाली लेज़र मशीन पिछले काफ़ी समय से खराब पड़ी है। जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

इस योजना की हकीकत दिनांक 20 फरवरी 2014 को उस वक़्त देखने को मिली जब बल्लभगढ़ से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने कंधे की टूटी हुई हड्डी का इलाज करवाने आए और लम्बी लाइनों के बाद कमरा नम्बर 19 में डॉक्टर गौड़ के पास चेकप के लिए अंदर गए और डॉक्टर ने उन्हें एक्सरा करवाने के लिए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति जब एक्सरे रूम में एक्सरा करवाने के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि एक्सरे नहीं हागा क्योंकि उनके पास एक्सरे फिल्म नहीं है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वह पी.एम.ओ. कृष्ण कुमार से मिलने पहुंचे और पी एम ओ ने भी उनके आगे एक्सरे फिल्म न होने का रोना रोया। और उन्हें बाहर से एक्सरे करवाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ा। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला जो दवाई लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी और जब उसका नम्बर आया तो उन्हें जवाब मिला कि अभी डॉक्टर द्वारा लिखी दवाई मौजूद नहीं है।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जबसे गुड़गांव को वेयर हाउस बनाया है तभी से अस्पताल में पूरी दवाईयों का स्टॉक समय पर नहीं आता जबकि गुड़गांव को वेयर हाउस इसलिए बनाया गया था कि वह फ़रीदाबाद के काफ़ी निकट है। गुड़गांव से अन्य छ: ज़िलों को भी दवाई सप्लाई की जाती है। हैल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों व बादशाह खान अस्पताल के डॉक्टरों, अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सरकार को लाखों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जबसे गुड़गांव को वेयर हाउस बनाया है तभी से अस्पताल में पूरी दवाईयों का स्टॉक समय पर नहीं आता जबकि गुड़गांव को वेयर हाउस इसलिए बनाया गया था कि वह फ़रीदाबाद के काफ़ी निकट है। गुड़गांव से अन्य छः ज़िलों को भी दवाई सप्लाई की जाती है। हैल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों व बादशाह खान अस्पताल के डॉक्टरों, अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सरकार को लाखों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है।

इन सब की मिली भगत के चलते सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपलब्ध ट्रेडरों द्वारा दवाईयां न लेकर लोकल ट्रेडरों से दवाईयों की कुटेशन उपलब्ध करवा कर दवाईयां खरीदी जा रही है। इसके साथ ही बादशाहखान अस्पताल के वाटर कूलर भी खराब पड़े हैं। दूसरी तीसरी मंजिल पर साफ पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते मरीज़ों व उनके साथ देखभाल के लिए आए परिजनों को ग्राउंड फ़्लोर पर पानी पीने के लिए आना पड़ता है। वार्ड के फटे बिस्तर, गन्दी चादरें और मैलेरिया विभाग व सिविल सर्जन कार्यालय की बन्द पड़ी सिवर लाइने अस्पताल प्रशासन की बेहतर सुविधा देने के दावों की पोल खोल रहे हैं।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 फरवरी 2014 के अंक में स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाशित लेख पढ़ने को मिले। 'आप से बाहर दिल्ली पुलिस आपे से बाहर केजरीवाल', 'दिल्ली पुलिस का बंदा केवल मुनाफ़े का धंधा', 'हत्या में दो बेगुनाह जेल में : सैशन जज ने सीपी से रिपोर्ट मांगी', 'ईमानदार एस.पी. ने, 19 लाख की कोठी खरीदी' तथा 'चोर मचाये शोर : ऊंट बैठेगा किस ओर' लेखों द्वारा पुलिस महकमें में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस की कार्यशैली को उज़ागर किया गया है। यह पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक शासन की देन है। यह पुलिस बल आम लोग़ों के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा संभ्रांत, बाहुबली, माफ़िया व शासक वर्ग की सुरक्षा के लिए बना है। पुलिस शासक वर्ग का वह प्रमुख हथियार है जिसका उपयोग वह आम लोग़ों का दमन और उन पर अत्याचार करने के लिए करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस बल सबसे भ्रष्ट है। इसमें पूरी तरह बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे इसकी मानसिकता में बदलाव हो और यह आम लोग़ों के हित में काम कर सके। एक अन्य लेख 'अवैध निर्माण :नगर निगम अधिकारियों की लूट का बड़ा स्रोत' द्वारा नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा भूमाफ़ियाओं की मिलीभगत को स्पष्ट किया गया है। अवैध निर्माण व सरकारी ज़मीनों पर भूमाफ़ियाओं द्वारा कब्ज़ा करने से ही तो नगर निगम, हूडा व पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की आय होती है। लेख 'आसाराम : अन्यायी व्यवस्था का एक बगुला भगत' में आसाराम, रामदेव, रविशंकर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, स्वामी प्रेमानंद, तान्त्रिक चन्द्र स्वामी, सांईबाबा, सुधांशु महाराज जैसे अनेक ढोंगियों द्वारा फैलाये जा रहे अन्ध विश्वास और उनके द्वारा किए जा रहे शोषण की तरफ़ आम जनता का ध्यान आकर्षित किया गया है। अभी फरवरी के पहले सप्ताह में हिंदुओं के प्रख्यात तीर्थ स्थल बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी (रावल) केशयन नम्बूदरी को दक्षिणी दिल्ली के एक होटल के कमरे में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है। ऐसे ढोंगियों से तभी मुक्ति मिलेगी जब पूंजीवादी व्यवस्था बदलेगी। इसके लिए एक लम्बी लड़ाई लड़नी होगी। ''टोल खोल रहा 'हुड्डा' के विकास की पोल' लेख द्वारा टोल लगाने के औचित्य पर सवाल खड़ा करके सराहनीय कार्य किया गया है। सड़क, नहर, पुल आदि बनाना राज्य का कर्त्तव्य होता है जिसके लिए राज्य जनता से टैक्स वसूल करता है। किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के समय रोड टैक्स वसूल किया जाता है, उसके बाद टोल टैक्स लगाना अनैतिक व गैर कानूनी है। टोल टैक्स लगाना पूंजीवादी व्यवस्था की परिकल्पना है। इससे पहले कभी टोल टैक्स नहीं लगाया जाता था। लेख 'दंगों में जलता रहा मुजफ़्फ़रनगर, दोषी कौन ?' द्वारा मुजफ़्फ़र नगर जैसे दंगों में विभिन्न पक्षों की साम्प्रदायिक भूमिका का सटीक विश्लेषण किया गया है। वास्तव में राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए विभिन्न साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों व संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिक दंगे प्रायोजित किए जाते हैं जिनमें कुछ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पूरी भागीदारी होती है। स्थाई स्तम्भों 'कविता' व 'व्यंग्य' द्वारा आम लोग़ों के समसामयिक मुद्दों को उठाने से मज़दूर मोर्चा का कलेवर और आकर्षक हो गया है।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 16-28 फरवरी 2014 के अंक में देश व समाज की समस्याओं से संबंधित लेख पढने को मिले। 'सोनिया द्वारा ई एस आई सी अस्पताल का उद्घाटन: मज़दूरों से धोखा' 'फ़रीदाबाद के अस्पतालों की दुर्दशा ज़्यों की त्यों', 'मेडिकल कॉलेज चल पाने की कोई संभावना नहीं' तथा 'स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा करने में हरियाणा सरकार भी पीछे नहीं' लेखों द्वारा ई एस आई सी तथा सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा व प्रशासन की लापरवाही की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। वास्तव में केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने जन कल्याण की नीतियों की अवहेलना शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। कॉर्पोरेट घराने आये दिन सुपर स्पेशलिटि अस्पताल खोलते जा रहे हैं। जिनमें उनको मोटी कमाई होती है। ये अस्पताल विदेशी, अमीर तथा बीमा युक्त मरीज़ों के लिए हैं, परंतु गरीब मरीज़ तो उधर झांक भी नहीं सकते। सबसे बुरी हालत तो मज़दूरों की है जिन पर दोहरी मार पड़ती है। लेख 'दिल्ली में लूटने हेतु बनी बिजली कम्पनियां' में बिजली कम्पनियों की धींगामस्ती के बारे में आंकड़ों सहित विस्तृत जानकारी दी गई है। यह तो निजी क्षेत्र की देन है क्योंकि निजी क्षेत्र में स्थापित कम्पनियों/उद्यमों का प्रमुख उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना है। दिल्ली की तत्कालीन 'आप' पार्टी की सरकार ने दिल्ली की इन बिजली कंपनियों की नकेल कसने की प्रक्रिया प्रारम्भ करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने से पहले ही त्यागपत्र देकर जनता को मझदार में छोड़ दिया। अब टाटा बिजली कम्पनी ने तो स्ट्रीट लाईट काटनी शुरू कर दी है। 'व्यर्थ नहीं जाएगी डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की शहादत' तथा 'डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या ' लेखों द्वारा धार्मिक ठेकेदारों द्वारा प्रचारित व स्थापित अन्धविश्वासों तथा इनके विरुद्ध संघर्ष और उसके परिणामों का सटीक विश्लेषण किया गया है। अन्धविश्वास के विरुद्ध केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगने के बावजूद सती प्रथा का महिमा मंडन किया जा रहा है। इसके लिए प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक विचारधारा युक्त लोग़ों को एकजुट होकर वैज्ञानिक विचारधारा के लिये जनता में चेतना जागृत करनी होगी। एक अन्य लेख 'संस्कृति के द्वन्द में आधुनिक नारी' में नारी मुक्ति आन्दोलन किस प्रकार भोगवादी संस्कृति में उलझ कर रह गया है का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है जिसमें पुरुष और स्त्रियों की मानसिकता नहीं बदली है आवश्यकता है पुरुष और स्त्री दोनों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। बम धमाके व साम्प्रदायिक दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ अक्सर रहा है जिसका वर्णन पीछे गठित कई आयोगों की जांच रिपोर्ट में मिलता है। इसका नवीनतम खुलासा लेख 'असीमानंद से कौन डरता है' में असीमानंद ने 'कारवां' की पत्रकार गीता रघुनाथ को दिए गए साक्षात्कार में किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर कार्यवाही न होने का कारण सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति का न होना होता तथा प्रशासन 'आई ए एस व आई पी एस' में उच्च स्तर पर इनके शुभ चिन्तकों का बैठा होना है। इसका ताज़ा उदाहरण केन्द्रीय गृह सचिव आर.के.सिंह तथा बम्बई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह का स्वेच्छा सेवा निवृति लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। इससे स्पष्ट है कि इन जैसे अन्य लोग अपने सेवा काल में भाजपा तथा साम्प्रदायिक संस्थाओं की विचारधारा के हमदर्द रहे हैं तो साम्प्रदायिक संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कैसे करने देते।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता